रविवारीय

संवाद व कुटनीति से ही समाधान-मोदी

राजीव खण्डेलवाल
(लेखक कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल नगर सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

मध्य-पूर्व एक बार फिर वैश्विक अस्थिरता के केंद्र में है. ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम पर चल रही बातचीत निर्णायक चरण में पहुँचती दिख रही थी. जैसा 26 फरवरी को ओमान के विदेश मंत्री द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति की बात कही गई थी. तब अचानक 28 फरवरी को अमेरिका द्वारा ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई ने पूरे समीकरण को ही बदल दिया. इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उक्त ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को निष्क्रिय करना, क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना तथा तथाकथित प्रतिरोध नेटवर्क को कमजोर करना बताया. मीडिया में दावा किया गया कि यह सैन्य कार्रवाई अमेरिका ने ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर जो ट्रंप प्रशासन में विशेष शांति दूत की भूमिका में है, विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री की सलाह पर इजराइल के कहने से की गई. परन्तु लगभग 27 दिनों के संघर्ष के बाद भी कोई भी लक्ष्य की स्पष्ट प्राप्ति नहीं हो सकी है. उलटे, अमेरिका द्वारा अनावश्यक लादे गए इस युद्ध ने विश्व को एक ऐसे संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है, जहाँ से निकलने का मार्ग अभी धुंधला दिखाई देता है.

इस युद्ध की एक उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि ईरान ने प्रत्यक्ष आक्रामकता के बजाय रक्षात्मक प्रतिरोध का उद्देश्य सामने रखकर प्रतिक्रियात्मक रणनीति अपनाई. ईरान ने पहले हमला करने से परहेज किया और हर सैन्य आक्रमण कार्रवाई का प्रत्युत्तर उसी अनुपात में देने की नीति अपनाई. इसने युद्ध को पूर्ण विस्तार लेने से कुछ हद तक रोके रखा. ट्रंप से मिली हमलों की धमकियों के मामले में भी ईरान ने यही नीति अपनाई. सैन्य संघर्ष का प्रभाव केवल क्षेत्रीय स्तर तक सीमित न रहकर वैश्विक स्तर पर होकर फैल रहा है. कच्चे तेल और

एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव, होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात में बाधा, वैश्विक महंगाई में संभावित वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता, भारत सहित अधिकांश देश इस प्रभाव व दुष्परिणाम से अछूते नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में स्वीकारा यह संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है. भारत के संबंध अमेरिका, इजरायल, और ईरान तीनों से ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण व अच्छे रहे हैं. खासकर प्रधानमंत्री मोदी के जमाने में इजराइल व अमेरिका से प्रगाढ़ व प्रेसीडेंट ट्रंप से बेहद व्यक्तिगत संबंध स्थापित हुए हैं, जिसने रूस-भारत संबंध को भी एक कदम पीछे छोड़ दिया. प्रधानमंत्री मोदी जब पिछली बार वर्ष 2016 में ईरान गये थे, तब उन्होंने यह कहा था कि दोनों देशों की दोस्ती नई नहीं है, बल्कि इतिहास जितनी पुरानी हैं. भारत के व्यापारिक फायदे के लिए चाबहार बंदरगाह विकास, व्यापार-परिवहन ट्रांजिट समझौते हुए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की कूटनीति अपनाने की अपील की है. यद्यपि इसके पीछे शायद उनकी सोच वहां रह रहे एक करोड़ से अधिक भारतीयों की सुरक्षा व उर्जा आपूर्ति रही है. आक्रमणकारी अमेरिका के ईरान पर किए हमले की प्रधानमंत्री ने आलोचना नहीं की, जो करनी चाहिए थी. खासकर तब, जब वे गल्फ देशों में स्थित अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान की बमबारी की आलोचना कर रहे है. तब मोदी निष्पक्ष नहीं दिख सके. स्पष्ट है, इस कारण वे देश के विपक्ष की आलोचनाओं का शिकार भी हुए प्रधानमंत्री का टीवी 09 समिट में दिया गया यह कथन कि भारत ने फैसले लेने का सार्मथ्य दिखाया है, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वह तथ्यों के विपरीत है. वस्तुत: भारत की विदेश नीति में परंपरागत रूप से रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है. परन्तु वर्तमान में इसका अभाव सा दिखता है.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खे ?ा का पत्रकार वार्ता में भारत के चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना साहब बीबी और गुलाम पोस्टर का इस्तेमाल कर उन्हें गुलाम कहना बेहद शर्मनाक है. इसे किसी भी रूप में कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है. वास्तव में यह कांग्रेस की गुलामी की कार्यशैली की प्रवृत्ति का अवतरण है. इस कथन की सर्वत्र घोर निंदा की जानी चाहिए थी.

इसके परिणामों व दुष्प्रभावों का आगे हम अध्ययन करते हैं. 1. सबसे बड़ी भूल जो भारत की ओर से हुई, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई पर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री द्वारा शोक व्यक्त न करना, जबकि पाकिस्तान ने किया. 5 दिन बाद ईरानी दूतावास जाकर भारत के विदेश मंत्री ने शोक संदेश लिखा. इसके पूर्व वर्ष 2024 में ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था. 2. लगभग 168 स्कूल के बच्चे अमेरिका-इजरायल द्वारा मौत के घाट उतारे जाने पर भारत द्वारा कोई आलोचना न करना, खेद जनक है. मात्र गहरी शोक संवेदना व्यक्त की. उक्त कृत्य अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन भी है. 3. भारत को रूस से सस्ते दरों पर तेल मिल रहा था. लेकिन अमेरिका के दवाब के चलते शैन: शैन: क्रय बंद करना पडा. विश्व गुरू बनने के मिशन के चलते अमेरिका की परमिशन से रूस से फिर तेल खरीदना चालू किया. इसमे कोई शक नहीं है कि मोदी के माई फ्रेड, अबकी बार ट्रंप सरकार, कहकर जो घनिष्ठ संबंध बनाये थे, उसका फायदा भारत को नहीं मिला, बल्कि अमेरिका ने भारत को मानमर्दित कर एकतरफा नाजायज फायदा लिया. इससे हमारे रूस व ईरान से सौहार्द संबंधों को भी नुकसान पहुंचा. 4. हमारे यहां कहावत है न पुलिस की दोस्ती अच्छी न दुश्मनी. उसी प्रकार का कथन अमेरिका के बाबत कहा जाता है. अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनी और भी खराब. अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना जानलेवा है. वर्तमान में यह देखने को मिल रहा है. पहले भी वर्ष 1971 के बांग्लादेश युद्ध में हमने देखा, अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता के लिए सातवां बेड़ा भेजा था. 5. यद्यपि नरेन्द्र मोदी ईरान के राष्टपति से बार बार बातचीत कर संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी अभी यह सुखद परिणाम आया है कि ईरान ने जिन पांच देशों को होर्मुज समुद्री में निर्बाध रास्ता दिया है जिसमें भारत भी शामिल है. 6. ईरान के संवैधानिक मान्यता प्राप्त पद सर्वोच्च नेता अली खामेनेई जो सिर्फ ईरान के ही नहीं बल्कि शिया संप्रदाय के विश्व के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं, की हत्या की भर्त्सना किए बिना, उन्हे श्रद्धांजलि दिये बिना, ईरान के घाव शायद ही भरें. बल्कि कहीं न कहीं बातचीत में वे घाव हरे हो जाते है. भारतीय संस्कृति के झंडेबरदार मोदी ऐसा मानवीय कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, समझ से परे है, जो उन्हें करना चाहिए था. देश में इस संकट के कारण पुन: कोरोना स्थिति आने की आशंका दिख रही, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता को तैयार हो जाना चाहिए. दुर्भाग्यवश इस बयान ने देश में एक भय की भ्रम की भावना पैदा हो रही है.

> पिछले 14 महीने से भारत की अमेरिका के प्रति नीति वर्ष 2025 में ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी के ट्रंप के दबाव में आने से गुटनिरपेक्ष नीति का अगुवा करने वाले भारत की विदेश नीति की दिशा बदलने से वह भारतीय हितों को प्रभावी रूप से साध नहीं पा रही है. यह किस दबाव में? अलग विषय है. लेकिन निश्चित रूप से 15 महीने के ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ट्रंप के भारत व मोदी के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर दिये गये बयानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ट्रंप भारत पर टर्म डिक्टेट कर रहा है. लगभग हर बार ट्रंप ने भारत की संप्रभुता, सार्वभौमिकता पर आक्रमण कर अपमानित, निम्नतर करने की लगातार कोशिश की है. इससे जहां हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, वहां हमारी एक सार्वभौमिक मजबूत राष्ट्र की छाप पर बडा धक्का लगा है.

बिहार में सत्ता का गणित, संकेत और हवा

श्याम यादव

बिहार की राजनीति को समझने के लिए केवल चेहरे नहीं, बल्कि समीकरण देखने पड़ते हैं. यहाँ जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव, गठबंधन की मजबूरियाँ और केंद्रीय राजनीति सब मिलकर अंतिम फैसला तय करते हैं. इस समय तीन बड़े समीकरण एक साथ काम कर रहे हैं, गठबंधन संतुलन, जातीय प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की स्वीकार्यता. सम्राट चौधरी का नाम जहाँ ओबीसी नेतृत्व को मजबूत करता है, वहीं जदयू अपने सामाजिक आधार को बनाए रखने के लिए किसी वैकल्पिक चेहरे या फॉर्मूले की तलाश में दिखती है. गणित में 'दो और दो' का जवाब तय होता है, राजनीति में नहीं. यहाँ सवाल हल होने से पहले ही जवाब बदलने लगते हैं. बिहार की मौजूदा राजनीति इस वाक्य को लगभग साकार करती दिख रही है. घटनाएँ तेज है, चेहरे सक्रिय हैं, बयान लगातार आ रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष जैसे किसी अदृश्य विराम में अटका हुआ है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन भरना इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मोड़ है. यह कदम केवल एक व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता संरचना में संभावित बदलाव का संकेत भी है. अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि वे राज्य की सक्रिय कार्यपालिका की राजनीति से एक कदम पीछे हट सकते हैं. लेकिन जैसे ही यह संभावना मजबूत हुई, सबसे बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ, उनकी जगह कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी की ओर से सम्राट चौधरी का नाम लंबे समय से चर्चा में है. प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका संगठन पर मजबूत पकड़ है. पिछले कुछ महीनों में उनके

सार्वजनिक कार्यक्रम, भाषण और पार्टी मंचों पर उनकी सक्रियता ने यह संकेत बार-बार दिया है कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं. दिलचस्प बात यह है कि खुद नीतीश कुमार ने भी कई मौकों पर सम्राट चौधरी के प्रति सकारात्मक संकेत दिए हैं. कभी सार्वजनिक मंच पर प्रशंसा, तो कभी उनके कंधे पर हाथ रखकर राजनीतिक संदेश देना. लेकिन जब औपचारिक घोषणा की बात आती है, तो भाजपा एक कदम पीछे हट जाती है. यह रणनीति नई नहीं है. भाजपा अक्सर ऐसे मौकों पर सस्पेंस को एक राजनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करती है. नाम को तय करने के बजाय चलने देना पार्टी को कई विकल्प खुले रखने का अवसर देता है, चाहे वह गठबंधन संतुलन हो, जातीय समीकरण हो या केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम मुहर.

उधर जनता दल (यूनाइटेड) इस पूरे सस्पेंस को खत्म करने के बजाय और गहरा कर रही है. पार्टी के नेताओं के बयान लगातार यह संकेत दे रहे हैं कि अभी कुछ भी तय नहीं है. यहाँ तक कि यह भी नहीं कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा या जदयू का. यह रुख केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा लगता है. जदयू यह स्पष्ट करना चाहती है कि गठबंधन में उसकी भूमिका अभी भी केंद्रीय है और वह केवल जूनियर पार्टनर नहीं है. इसके पीछे एक और महत्वपूर्ण पहलू है बिहार की जातीय और सामाजिक राजनीति. जदयू अपने पारंपरिक वोट बैंक, खासकर अति पिछड़ा और महादलित वर्ग, को यह संदेश देना चाहती है कि सत्ता में उसकी भागीदारी कम नहीं होने वाली. इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नया और दिलचस्प नाम तेजी से उभरा है निशांत कुमार.

अब तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार ने 8 मार्च को जदयू की सदस्यता लेकर अचानक सुर्खियां बटोर लीं. उनकी सक्रियता में जो तेजी आई है, वह ध्यान खींचने वाली है. कुछ ही दिनों में वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखने लगे, लोगों से मुलाकात करने लगे और राजनीतिक आयोजनों जैसे इफ्तार पार्टियों में सहज रूप से शामिल होते नजर आए. और फिर नारे बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो ने इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बना दिया. लेकिन, राजनीति में हर नारा वास्तविक संभावना का संकेत नहीं होता. कई बार यह केवल टेस्टिंग द वाटर्स होता है. यानी माहौल को परखने की कोशिश. निशांत कुमार के मामले में भी फिलहाल यही अधिक संभावित लगता है. उन्हें सीधे मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री की कतार में खड़ा मान लेना जल्दबाजी होगी. बिहार की राजनीति में वंशवाद के उदाहरण जरूर हैं, लेकिन हर उदाहरण सफल हो, यह जरूरी नहीं. बिहार की राजनीति को समझने के लिए केवल चेहरे नहीं, बल्कि समीकरण देखने पड़ते हैं. यहाँ जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव, गठबंधन की मजबूरियाँ और केंद्रीय राजनीति सब मिलकर अंतिम फैसला तय करते हैं. इस समय तीन बड़े समीकरण एक साथ काम कर रहे हैं, गठबंधन संतुलन, जातीय प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की स्वीकार्यता. सम्राट चौधरी का नाम जहाँ ओबीसी नेतृत्व को मजबूत करता है, वहीं जदयू अपने सामाजिक आधार को बनाए रखने के लिए किसी वैकल्पिक चेहरे या फॉर्मूले की तलाश में दिखती है.

ईरानी राष्ट्रवाद से हार गई दुनिया

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने
(विदेशी मामलों के जानकार)

> संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने भी ईरान ने सैन्य,कूटनीतिक और प्रॉक्सी नेटवर्क के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए रखी है. विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र और हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर उसकी पकड़ उसे रणनीतिक बढ़त देती है. ईरान ने यह जरूर प्रदर्शित किया है कि वह एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उसकी सैन्य,वैचारिक ताकत हो या रणनीति,दुनिया को यह संकेत देने में कामयाब रही है की पश्चिम एशिया की राजनीति में उसकी भूमिका निर्णायक बनी रहेगी. ईरान की रणनीति ने उसकी क्षमता और प्रभाव को बखूबी उजागर किया है,हालांकि अभी इसे पूर्ण वर्चस्व के दूर लेकिन एक जटिल शक्ति संतुलन के रूप में अनुभव किया जा सकता है.

ईरान की मजबूती का एक प्रमुख आधार उसका गहरा और ऐतिहासिक राष्ट्रवाद रहा है. ईरान में राष्ट्रवाद राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत है तथा इसमें सांस्कृतिक,धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान का सम्मिलित प्रभाव है. दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में शामिल फारसी सभ्यता की प्राचीन विरासत लोगों में गौरव और आत्मसम्मान की भावना जगाती है. 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति ने इस राष्ट्रवाद को और मजबूत किया तथा आम जनता ने संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के खिलाफ एकजुट होकर अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित की. इसके बाद से ईरान ने आत्मनिर्भरता,स्वदेशी तकनीक और सैन्य क्षमता पर जोर दिया,जो उसके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है. बाहरी दबावों,आर्थिक प्रतिबंधों और संघर्षों के बावजूद,ईरानी समाज अपनी संप्रभुता और अस्मिता की रक्षा के लिए एकजुट रहता है. यही कारण है कि इजराइल और पश्चिमी देशों के साथ तनाव के बावजूद ईरान कमजोर नहीं पड़ा है. दरअसल ईरान का राष्ट्रवाद उसे आंतरिक स्थिरता,राजनीतिक दृढ़ता और वैश्विक स्तर पर प्रभाव बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है.

ईरान एक बड़ा,जटिल और सैन्य रूप से सक्षम देश है जहां अमेरिका की सीधे कब्जे की रणनीति बेहद कठिन और जोखिमपूर्ण मानी जाती है. ईरान का इतिहास बताता है कि यह बाहरी हस्तक्षेपों के बावजूद अपनी संप्रभुता बनाए रखने में सक्षम रहा है. एंग्लो-सोवियत आक्रमण के दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान में सैन्य हस्तक्षेप किया,लेकिन यह स्थायी कब्जे में कभी नहीं बदल सका. इसी तरह,ईरानी इस्लामी क्रांति ने यह दिखाया कि बाहरी प्रभाव के खिलाफ जनता कितनी तेजी से संगठित हो सकती है. ईरान की भौगोलिक स्थिति पहाड़ों,रेगिस्तानों और जटिल भूभाग से भरी पड़ी है और यह किसी बाहरी शक्ति के लिए लंबे समय तक सैन्य नियंत्रण को कठिन बना देती है. इसके अलावा,मजबूत राष्ट्रवाद,वैचारिक प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय नेटवर्क उसे और अधिक टिकाऊ बनाते हैं.

जब किसी देश में आर्थिक दबाव,प्रतिबंध या आंतरिक असंतोष होता है तो सरकारें राष्ट्रवाद को एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकती है. इससे लोगों का ध्यान आंतरिक समस्याओं से हटाकर बाहरी खतरे की ओर केंद्रित किया जाता है. इससे अस्थायी रूप से नाराजगी कम होती है और सरकार के प्रति समर्थन बढ़ सकता है. ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य भर्ती का व्यापक राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य नजर आता है. बसीज जैसे संगठन लंबे समय से युवाओं को जोड़कर राष्ट्रवादी और वैचारिक एकजुटता मजबूत करने का काम करते रहे है. वर्तमान परिदृश्य में ईरान और खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच बढ़ता तनाव पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है. यदि ईरान आक्रामक रुख अपनाते हुए खाड़ी क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने में सफल होता है तो इसका सीधा असर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों पर पड़ेगा. ईरान की सैन्य या रणनीतिक सफलता से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है.

अभी तक खाड़ी देशों को अमेरिका का सहयोग मिलता रहा है, जिससे वे ईरान के प्रभाव को संतुलित करते हैं. लेकिन यदि किसी संघर्ष में ईरान मजबूत होकर उभरता है तो यह धारणा कमजोर पड़ सकती है कि पश्चिमी समर्थन हमेशा निर्णायक रहेगा. इससे खाड़ी देशों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी. ईरान लंबे समय से सीधे युद्ध के बजाय क्षेत्रीय समूहों और सहयोगी ताकतों के माध्यम से प्रभाव बढ़ाने की नीति अपनाता रहा है. यदि उसे सफलता मिलती है तो वह इस रणनीति को और आक्रामक रूप से आगे बढ़ा सकता है,जिससे खाड़ी देशों के अंदरूनी सुरक्षा ढांचे पर दबाव बढ़ना तय है. खाड़ी देश वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के केंद्र हैं. यदि ईरान की स्थिति मजबूत होती है और वह समुद्री मार्गों,तेल आपूर्ति और कीमतों पर उसका प्रभाव बढ़ जाएगा. इससे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की आर्थिक और रणनीतिक स्वतंत्रता सीमित हो सकती है. राजनीतिक स्तर पर खाड़ी देशों को अपनी विदेश नीति में बदलाव करना पड़ सकता है. वे या तो ईरान के साथ समझौते की दिशा में बढ़ सकते हैं या फिर अधिक आक्रामक सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे. हाल के वर्षों में क्षेत्रीय कूटनीति में जो संतुलन बना था,वह फिर से अस्थिर हो सकता है.

ईरान में शिया पहचान और राष्ट्रवाद का मेल उसकी रणनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार है. यह केवल धार्मिक भावना नहीं,बल्कि राजनीतिक वैधता और सामाजिक एकजुटता का साधन भी है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और वैचारिक ढांचे के माध्यम से यह शिया राष्ट्रवाद आंतरिक स्तर पर शासन को मजबूत करता है और बाहरी स्तर पर एक प्रतिरोधी छवि बनाता है. जब किसी देश में यह भावना उफान पर होती है, जनता को और अधिक एकजुट कर देता है. इसी वजह से अमेरिका के लिए शासन परिवर्तन जैसे मंसूबे कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे है. ईरान में बाहरी हस्तक्षेप को राष्ट्रीय अस्मिता के खिलाफ माना जाता है जिससे आंतरिक विरोध भी कमजोर पड़ गया है. शिया राष्ट्रवाद और आक्रामक रणनीति निश्चित रूप से ईरान को मजबूत बनाया है और बाहरी शक्तियों के लिए चुनौती बढ़ा दी है. धार्मिक नेताओं और सैन्य कमांडरों के मारे जाने के बाद भी ईरान की स्थिरता और दृढ़ता यह दर्शाती है कि वहां राष्ट्रवाद और शिया धर्मवाद की जड़ें अत्यंत गहरी हैं.

व्यंग्य

इसक्यूज मी...

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

जब से छेदी बाबू को यह पता चला है कि बात बात पर एक्सक्यूज़ मी और थैंक्यू बोलना सभ्यता की निशानी है तो उन्होंने तय किया कि वे अब दुनिया को बता देंगे कि वह भी सभ्य इंसान हैं . दरअसल हुआ यह कि एक बार जब छेदी बाबू मेट्रो रेल में खड़े खड़े यात्रा कर रहे थे तब उनके कानों में एक मधुर आवाज गूंजी एक्सक्यूज़ मी. छेदी बाबू ने आवाज की दिशा में पलट कर देखा तो देखते रह गए . उनके पीछे एक सुंदर सी महिला, जिनके बाल कटे हुए थे और आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था . छेदी बाबू ने जब उन्हें देखा तो उनके दिल में गिटार बज उठी . वे तुरंत संभले और रास्ते से थोड़ा हट कर खड़े हो गए . वो मेडम उनसे रास्ता मांग रहीं थीं ताकि वो मेट्रो से नीचे उतर सकें . जब छेदी बाबू ने उन्हें रास्ता दे दिया तो वह फिर स्वर में मिठास घोल कर बोलीं - थैंक्यू .

थैंक्यू शब्द सुनते ही छेदी बाबू अचकचा कर निर्वाक्य हो गए .जब मेडम प्लेटफार्म पर उतर गईं तब छेदी बाबू के मुखारबिंद से हकलाते हुए धीमे स्वर में निकला थैंक्यू. .थैंक्यू . लेकिन तब तक मेट्रो एक झटके के साथ वैसे ही तेजी से आगे बढ़ गई जैसे ई-स्कूटी बिना आवाज किए सटाक से आगे बढ़ जाती है .

अपनी मेट्रो यात्रा के बाद जब छेदी बाबू वापस अपने शहर लौट आए . उनका शहर कोई बड़ा शहर तो नहीं था, हां वह गांव से बड़ा और शहर से काफी छोटा था . उसे बड़ा कस्बा कहा जा सकता है . पर यह उसके प्रति लगाव ही था कि वो वहां के बाशिंदों को शहर ही लगता था . जैसे सब को अपनी पत्नी में कभी माधुरी तो कभी हेमा नजर आने लगती है . यह भ्रम अक्सर रात में उस समय होता है जब एलईडी बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है . जिससे उनके चेहरे पर और ग्लो बढ़ जाता है . खैर शहर से लौटने के बाद छेदी बाबू लंबे समय बाद एक दिन मेरे घर आ धमके .

हैप्पी होली बोल कर हमें बधाई दी . नाश्ते का सम्मान किया और बोले इसक्यूज मी भाई साहब चाय और हो जाती तो मजा आ जाता . हमने कहा चिंता मत कीजिए पीछे - पीछे वह भी आ रही है . पर मैंने नोटिस किया कि जिस व्यक्ति ने कभी धन्यवाद नहीं बोला, उसने इसक्यूज मी, कैसे बोल दिया . ये मौसम परिवर्तन कैसे हो गया . यह शब्द तो गाली गलोच करने के बाद भी हमारे सांसद- विधायक और नेता कभी नहीं बोलते, वह अदना से छेदी बाबू ने कैसे बोल दिए . यह तो ग़ज़ब ही हो गया . छेदी बाबू में यह समझ और सभ्यता आखिर आई कहां से ?

भाई साहब के सामने टीवी डिबेट और विधायिकाओं के सदनों के वे दृश्य घूम गए . जिन दृश्यों में बहस के दौरान नेता गण एक दूसरे के खिलाफ नितांत अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते नज़र आते हैं . जब उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है तो वे बेशर्मी से इंकार कर देते हैं . यदि ऐसा करना मजबूरी ही हो जाए तो बड़ा एहसान जता कर कहते हैं कि उनके कथन से यदि किसी को दु :ख पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं . ऐसा नेताओं को क्षमा मांगने से इंकार करना उनकी सभ्यता की श्रेणी में आता है . ऐसे नेताओं का क्षमा मांगने का अपना ही स्टैंडर्ड होता है . वे केवल कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं . वरना हीलिंग चिलिंग फूंक फांक सब मेरे स्टाईल में अड़े रहते हैं . तब तक चाय भी आ चुकीं थी . छेदी बाबू ने एक जोरदार सुडूक की आवाज लगाने के बाद मेट्रो ट्रेन का वाक्या सुनाते हुए पूछा कि भाई साहब यह बताईए कि कुछ लोग बात बात पर इसक्यूज मी और थैंक्यू क्यों कहते हैं . हमने समझाया छेदी बाबू यह सभ्य और एजुकेटेड होने की निशानी है . ओह ये बात है ... भाई साहब अब से हमने यह फैसला किया है कि जो काम अब तक हमारे देश के नेता नहीं कर पाए वह काम अब हम दुनिया को करके दिखाएंगे . अब हम भी सभ्य बनेंगे .

छेदी बाबू ने थोड़ी देर सोच कर फिर से सवाल पूछा पर भाई साहब ये नेता लोग संसद और विधानसभाओं में क्यों नहीं सभ्यता से पेश आते? क्यों अभद्र और असंसदीय शब्दों का उपयोग करने के बाद भी माफ़ी नहीं मांगते? हमने कहा संस्कार की वजह से .इस तरह के नेताओं को न तो उनके परिवार से इस तरह के संस्कार मिले और न ही पार्टी से . पार्टी में शायद इनके नेता इनसे इसी भाषा में बात करते होंगे तो वह दूसरों से भी उसी भाषा में बात करते हैं . कल इनकी संतान भी इनसे इसी भाषा में बात करेंगे . इसे टिड फॉर टेड कहते हैं . छेदी बाबू बोले भाई साहब पर मजा तो हमारी प्रेम से पगी खड़ी भाषा में ही है . यदि बीच रास्ते में खड़े व्यक्ति को हटाना हो तो जो मज़ा यह कहने में है कि ओए बीच में क्यों ठाड़ा है, परे हट कर खड़ा हो जा . इस पर जो जवाब मिलता है वह भी मजेदार होता है, ओए ताऊ इत्ती तो जगे पड़ी है, थोड़ा टेड़ा होके निकलजा . सिर पै पैर धरकै जागा कै . भाई साहब को अपना बचपन याद आ गया जब स्कूल में मैडम ने सिखाया कि घर पर भी मम्मी-पापा से थैंक्यू और एक्सक्यूज़ मी कहा करो और कोई गलती हो जाए तो सॉरी बोला करो . पर हुआ इसका उलटा . पापा मम्मी ने सॉरी एक्सक्यूज़ मी और थैंक्यू कहने पर हड़का दिया . कहा बेटा यह शब्द तुम स्कूल में मैडम से ही बोला करो .यह शब्द पराए और अनजान लोगों से बोले जाते हैं, अपनो से नहीं . पढ़- लिखने का मतलब यह नहीं है कि अपना कल्चर भूल जाएं . अपने कल्चर में बड़ों के चरण स्पर्श किए जाते हैं और सम वयस्कों और छोटों से प्रेम किया जाता है .